मैडम, हमने पिछले दिनों केबल टी० वी० नेटवर्क बिल पास किया है और यह जो जी-टीवी, स्टार टीवी, बी०बी०सी० और जैन टीवी के कार्यक्रम हमारे घर घर में पहुंच रहे हैं और उसक माध्यम से शराब सेवन और तम्बाकू सेवन पर तरह तरह की बात आ रही है । इस पर रोक लगनी चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : मैडम, यह बिल्कुल ठीक नहीं है । ... (**व्यवधान**)...यह क्या बात है ?

†(ڈاکٹر سکندر بخت : میڈم یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ... "مراعات" ... یہ کیا بات ہے۔)

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am not blocking you. But, I am associating with him.... (*Interruptions*) .. मैडम, मेरा कहना यह है कि जो अभी केबल टी०वी० पर बिल पास किया गया है उसके तहत इस पर रोक लगनी चाहिए । ...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia , yesterday the Bill was passed in this House.
अभी आप लोग खामोश रहेंगे या नहीं ? ...(**व्यवधान**)...
The Bill has already been passed.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैडम, यह बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि उस पर रोक कैसे लगे, इस पर सदन को विचार करने की जरुरत है । तम्बाकू सेवन की और शराब सेवन की बात कहां उठ रही है ? ..... (**व्यवधान**) ....

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, may I raise my issue?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have called your name.

RE: GYAN PRAKASH COMMITTEE REPORT ON IMPORT OF SUGAR

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

SHRI S. JAIPAL REDDY: (Andhra Pradesh): Madam, this is the third Session in succession during which we are being obliged to refer to the question of swindling and bungling involved in the import of sugar this year. When we first raised it, we were under the impression that the matter was being looked into by the Public Accounts Committee. After that, the Session adjourned, the Public Accounts Committee was prevented from proceeding an inquiry into the sugar scandal. Before the Budget Session, the Govenment announced an inquiry by Mr. Gyan Prakash in a hurried and awkward manner. At that stage we protested against the inquiry. We said that Mr. Gyan Prakash was a retired C&AG and was not constitutionally entitled to inquire into anything at all. What was more, we pointed out at that time that Mr. Gyan Prakash was morally not qualified to look into it because he was Chairman of a company which received a sugar-mill licence. Even so, the Government proceeded with this very awkward form of an inquiry and the Government gave us to understand that this Committee report would, eventually, be made public, made available to the Parliament and the Parliament could discuss it. The Committee, headed by Mr. Gyan Prakash, submitted its report two months back which has been languishing with the Government for the last two months. And, today, we learn that the Cabinet Secretary, Mr. Surendra Singh, will be looking into it as a head of another committee. This is an outrageous development, apart from being a comical affair.

Madam, in the last Session, when we dicussed the question, I had pointed out that the 1994 sugar scandal was, in fact, a replication of the *modus operandi* adopted in 1989 expect that the scale of operation was magnified. To support this contention, I

place on the Table a copy of the CBI report which indicted the then Minister, Mr. Sukh Ram. I laid it on the Table of the House with your permission by authenticating it. And, today we have another report which is being withheld from the Parliament. We understand authentically that even Mr. Gyan Prakash had no option but to condemn quite a few in the Government, including the present Minister, Mr. Kalp Nath Rai I do not understand, Madam, whether we have a Cabinet of indicted ministers? People are wondering whether this is a Cabinet of scamsters and, of course, the Government do not take any action, do not submit an ATR on anything, on CBI, on Gyan Prakash Committee, or on JPC. But in the elections that were held in Andhra Pradesh and Karnataka, people have submitted their own ATRs. The people's ATR is before you. And yet you are unmoved. This Government goes underground and performs a vanishing act whenever it encounters any crisis.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Jaipal ji, other names are also there.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, what I am saying is that the Governments should place the Gian Prakash Committee Report on the Table of the House. The House should go ahead with discussing it immediately. Until a settlement on this question is reached, the House will not be in a mood to discuss anything, to transact any other business. I would like to make that clear.

श्री शंकर दयाल सिंह : (बिहार) : जो कुछ भी उन्होंने कहा है, हम लोग इनके साथ हैं और जब तक यहां पर रिपोर्ट नहीं रखी जायेगी और मंत्री जी को निकाला नहीं जायेगा, हम विवश हैं, जनतन्त्र की रक्षा के लिये, हम इस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे .... (**व्यवधान**) .... ।

उपसभापति : ऐसे अलफाज मत इस्तेमाल कीजिये .... (**व्यवधान**)

....I am not allowing

ये जो आप बोल रहे हैं, शंकर दयाल जी * के अलफाज यहां नहीं होते, निकाल दीजिये रिकार्ड से .... (**व्यवधान**)

No, I am not allowing. Do not shout.

श्री शंकर दयाल सिंह : ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट पर अखबारों में जनता की ओर से हर बार आ रहा है... (**व्यवधान**) आखिरकार महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि लोकतन्त्र कैसे चलेगा... (**व्यवधान**)

उपसभापति : लोकतन्त्र * कहकर नहीं चलेगा।

I am not allowing. I will not permit. Just a minute... (*Interruptions*)... Shankar Dayalji, however disturbed you might be, please do maintain the dignity. Do not forget that we are sitting in a very important House. There are certain etiquettes and traditions that we have to follow.

*का लफ्ज यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल रिकार्ड पर नहीं जायेगा। गुस्से का दूसरे तरीके से भी इजहार हो सकता है, बुरा-भला कहकर नहीं हो सकता।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने तो का नाम ही नहीं लिया।

उपसभापति : नाम लिया या नहीं लिया। I am not allowing... (*Interruptions*)

Please do not pressurise me to use my discretion.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहिबा, मैं शुक्रगुजार हूं, चेयरमैन

*Expunged as orders by the Chair.

श्री सिकन्दर बख्त

साहब का कि इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सदन साहिबा, यह जो एक लम्बी जंजीर है—करप्शन ऐट हाई प्लेसेज, कवर-अप्स—इसमें एक ताजातरीन कड़ी का आज इजाफा हो गया है। सदर साहिबा, जे०पी०सी० की रिपोर्ट आती है, जिसमें दोनों सदनों के लोग, हर पोलिटिक्स पार्टी के लोगों की नुमाइंदगी होती है। जे.पी.सी. की युननिमस रिपोर्ट आती है . . . (व्यवधान)

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ۔ میں شکر گزار ہوں چیرمین صاحب کا کہ انھوں نے میری درخواست قبول کی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ صدر صاحبہ یہ جو ایک لمبی زنجیر ہے کرپشن ایٹ ہائی پلیسیز کور اپس کی اس میں ایک تازہ ترین کڑی کا آج اضافہ ہو گیا ہے۔ صدر صاحبہ۔ جے۔ پی۔ سی۔ کی رپورٹ آئی ہے جس میں دونوں سدنوں کے لوگ۔ ہر پالیٹیکل پارٹی کے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جے۔ پی۔ سی۔ کی یونینی مس رپورٹ آئی ہے۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

श्री ईश दत्त यादव : (उत्तर प्रदेश) वही बोलेंगे।

श्री ईश दत्त यादव : : नाम लिख दीजिये।

उपसभापति : मैं नहीं लिखूंगी। नाम लिखने का काम मेरा नहीं है। जो नाम मेरे पास चेयरमैन साहब से क्लियर होकर आते हैं, मैं उसी के अनुसार चलती हूं। आप चेयरमैन साहब से परमीशन ले लीजिये।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मेरा कहना यह है कि खुदा जाने रूलिंग पार्टी के जहनों में क्या गुजरा है कि जे०पी० सी० की रिपोर्ट को ऐसा कर दिया, जैसे उसके कोई माने नहीं हैं। एक रिपोर्ट ये लेकर आये, जो रिपोर्ट थी ही नहीं, खुदा जाने क्या थी वह, उसको ऐक्शन टेकन रिपोर्ट का ऊंचा नाम दिया गया जिसमें किसी जगह कुछ लोगों पर इलजाम साबित हुए, एक इन्वैस्टिगेटिंग ऐक्टिविटी के बाद कुछ लोगों पर इलजाम साबित हुए और उन लोगों के गुनाहों पर परदा डालने के लिये इस किस्म की बैमानी, फिजूल, जिसका कोई मकसद नहीं, ऐसी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर आते हैं। इधर हाऊस में हमारे चेयरमैन साहब यह जिक्र करते हैं कि अगले सत्र में रिवाईज और मांडिफाईड रिपोर्ट लेकर यह सरकार तशरीफ लाएगी। साढ़े तीन महीनों में उस रिपोर्ट के बजूद की कोई सूरत-शक्ल दिखाई नहीं दी। फिर यहां बयान दिया गया कि 20 तारीख से पहले रिपोर्ट आयेगी। कोई इनसे सवाल नहीं करना चाहता कि जिस रिपोर्ट को साढ़े तीन तीन महीने में आप तैयार नहीं कर सके, तो इन चन्द दिनों में क्या कर

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

केंगे, उस रिपोर्ट के अन्दर । मगर नबूझकर इस सत्र के आखिरी हिस्से इसलिये लाना चाहते हैं कि उस पोर्ट पर बहस होने की गुंजाइश रहे बाकी । जब ज्ञान प्रकाश कमेटी यम हुई, इस हाऊस में मिनिस्टर हब का बयान सुना गया । अब खुदा ने उस बयान का सर और पैर कालना ही दुश्वार था कि उन्होंने । फरमाया और क्या कहा । जो इल्जाम ा-सीधा लगा था उसका कोई ाब नहीं मिल सका । पहले से ,पीछे र उस सिलसिले को ऐसे ही गदरबूद दिया गया कि ज्ञान प्रकाश कमेटी ैर हुई । ज्ञान प्रकाश कमेटी का ैर करना ही आपोजिशन के नजदीक ले ऐतराज था, जैसा कि हमारे जयपाल रेड्डी साहब ने कहा । उन्होंने कि यहां सुप्रीम कोर्ट के जज की पुरी मुकर्रर होनी चाहिये । लेकिन डोर से यह हरकत की गई कि जिस ी का दरायेरास्ते से ताल्लुक है, शुगर मिल से, उस आदमी के कर दिया गया । अब मैं यह कहना ा हूं कि वह गलत था । आपोजिशन ाराज किया कि ज्ञान प्रकाश साहब ुकर्रर नहीं करना चाहिये था । उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है वह हाऊस के सामने आती क्यों ? उसके बाद ताजातरीन यह ना देखने में आता है कि गर्वनमेंट-

› another panel on sugar scam.

ह मजाक बना दिया है कि पार्लि- का । यह पार्लियामेंट्री सिस्टम को करने का इरादा कर लिया है, कार ने । यह जानना चाहते हैं, हम । मैं बिल्कुल सौ फीसदी जयपाल रेड्डी जी की बात से मुताबित हूं कि यह बात आज साफ होनी चाहिये कि क्या यह सरकार पार्लियामेंट्री प्रेक्टिसेज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बुलडोज कर देना चाहती है ? क्या करना चाहती है ? जब तक ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट हाऊस में नहीं आयेगी, यह हाऊस नहीं चलने दिया जायगा, बिल्कुल नहीं चलने दिया जायेगा.... (व्यवधान).....।

उपसभापति : अगर हाऊस नहीं चलने देंगे, तो .....(व्यवधान)..

श्री सिकन्दर बख्त : बिल्कुल नहीं चलने देंगे....(व्यवधान) ..... तमाम पार्लियामेंट्री सिस्टम के चलने में रुकावट डाली है इस सरकार ने । .....(व्यवधान).....

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

سے یہ حرکت کی گئی کہ جس آدمی کا براہ راست تعلق ہے شوگر مل سے۔ اس آدمی کے سپرد کر دیا گیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط تھا۔ اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ "گیان پرکاش صاحب کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کی جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے وہ ہاؤس کے سامنے آئی کیوں نہیں۔ اس کے بعد تازہ ترین یہ شاخسانہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گورنمنٹ "سیٹس اپ انادر پینل آف شوگر اسکیم" یہ مذاق بنا دیا ہے پارلیمنٹ کا۔ یہ پارلیمنٹری سسٹم کو روٹن کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس سرکار نے۔ یہ جاننا چاہتے ہیں ہم۔ میں بالکل سو فیصدی جے پال ریڈی جی کی بات سے متفق ہوں کہ یہ بات آج صاف ہونی چاہیے کہ کیا یہ سرکار پارلیمنٹری پروسیجر کو۔ پارلیمنٹری سسٹم کو بلڈوز کر دینا چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہے۔ جب تک گیان پرکاش کمیٹی کی رپورٹ ہاؤس میں نہیں آئے گی۔ یہ ہاؤس نہیں چلنے دیا جائے گا۔ بالکل نہیں چلنے دیا جائے گا۔... "مداخلت"

آپ سمجھا بھی: اگر ہاؤس نہیں چلنے دیں گے تو... "مداخلت"...

شری سکندر بخت: بالکل نہیں چلنے دیں گے... "مداخلت"... تمام پارلیمنٹری سسٹم کے چلنے میں رکاوٹ ڈالی ہے اس سرکار نے... "مداخلت"...

ایکشن ٹیکن رپورٹ لیکر آتے ہیں۔ ادھر ہاؤس میں ہمارے چیئرمین صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگلے سترین ریوائزڈ اور ماڈی فائیڈ رپورٹ لے کر یہ سرکار تشریف لائیگی۔ ساڑھے تین مہینوں میں اس رپورٹ کے وجود کی کوئی صورت شکل دکھائی نہیں دی۔ پھر یہاں بیان دیا گیا کہ ۲۰ تاریخ سے پہلے رپورٹ آئے گی۔ کوئی ان سے سوال نہیں کرنا چاہتا کہ جس رپورٹ کو ساڑھے تین مہینے میں آپ تیار نہیں کر سکے۔ تو ان چند دنوں میں کیا کر سکیں گے اس رپورٹ کے اندر۔ مگر جان بوجھ کر اس ستر کے آخری حصے میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس رپورٹ پر بحث ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ باقی جب گیان پرکاش کمیٹی قائم ہوئی۔ اس ہاؤس میں منسٹر صاحب کا بیان سنا گیا۔ اب خدا جانے اس بیان کا سر اور پیر نکالنا ہی دشوار تھا کہ انھوں نے کیا فرمایا اور کیا کہا۔ جو ایم پی جا سادہ لگا تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ پہلے سے پیچھے ہٹ کر اس سلسلہ کو ایسے غدر بود کر دیا گیا۔ اور گیان پرکاش کمیٹی مقرر ہوئی۔ گیان پرکاش کمیٹی کا مقرر کرنا ہی اپوزیشن کے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ جیسا کہ ہمارے دوست جے پال ریڈی صاحب نے کہا۔ انھوں نے کہا کہ یہاں سپریم کورٹ کے جج کی انکوائری مقرر ہونی چاہیے۔ یہ ایک ڈرامہ

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): The Government has to be transparent.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Biplab Dasgupta.

DR. BIPLAS DASGUPTA (West Bengal): Madam, my two colleagues on my right have raised very important issues, and I would like the Government to respond to it. We have been raising this issue since the last session. And you will recall, Madam, that in the last session when the issue was raised, we were told, "a Committee has been set up. You don't worry. Allow the Committee to function. The Report of the Committee would be placed before the Parliament." That was the impression given. Now why should n't the report of the Committee be placed before the House? It is certainly a question of corruption in high places. But many other issues are also coming up, and we would like all these issues to be discussed. If these are already there in the report, that would held. If not, we want these to be discussed.

Madam, one major issue is the question of collective Ministerial responsibility because, on this issue of sugar, all kinds of directions came. A Cabinet decision was made. The Minister said something different. The whole Government was speaking with many, many voices. Then, the second issue is the question of relationship between the Minister and the bureaucrats. Even in the Department of Food, the Minister was making one kind of statement, the Secretary was making another kind of statement.

AN HON. MEMBER: The Cabinet Secretary also.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Yes, the Cabinet Secretary also. The third question is about the decision-making process of the Government. Who is the boss? Sometimes we do not understand whether we have a Government or not because the decision-making process does not seem to be functioning. The Cabinet takes a decision. Then the Department stalls the decision. Then again the decision is reiterated and the Minister again stops the execution of the decision. The Minister comes to the House and he makes a personal statement. Madam, you remember that in the last session, when the Minister spoke for a long time, what did he speak? For a long time he was talking nothing. Nothing came out of it. But personal references came out, apologies were given. But my point is, when the Minister speaks here, he speaks not only for the Department concerned, but also for the Government as a whole.

Somehow, we have this problem in understanding as to how decisions like this are taken.

Then, the fourth issue came up as to how the estimates were made, how the statistical estimates were made. How did one estimate the demand for sugar in a particular year? How did one estimate.. (*Time-bell*) Just two- three points more, Madam. The question was: how did one estimate the production in the country? Then, there was also the question about the imports needed, the quantum to be imported. All these things remain unclear from the statement which had been made by the hon. Minister.

The fifth issue was about the manipulation of prices. There were serious allegations that the imports were undertaken in order to help the sugar lobby in the country to raise the prices, exploit the consumer and make profits.

The next one was the question of the close relationship between the Minister and the sugar lobby. Some of us gave references which had indicated the relationship, the intimate relationship, between the sugar lobby and the Minister, at the personal level.

Then the question came up as to the way of functioning of the Minister. Was he functioning on behalf of the Government and the country, or, was he functioning on behalf of the sugar lobby? This was the question which came up. Was he functioning on behalf of the sugar lobby and working for their interests? (*Time-bell rings*) This ques-

[Dr. Biplab Dasgupta]

tion was also raised because this particular Minister had been saying many, many things. He had said that the price of sugar should be Rs. 20 per kg. He had said that this was the legitimate price for sugar.

Then there was the question of the cover-up effort. Madam, you would recall that in the Watergate case, the initial offence was, of course, serious.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no debate taking place here, Mr. Dasgupta. Please be brief.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I would sit down in just one more minute, Madam. I promise you.

In the Watergate case, the initial offence was, of course, serious. But much more serious was the cover-up. As a result of this, President Nixon had to go. Now, in this case, we have the feeling that not only the Minister of Food, but the whole Government is guilty of cover-up. They are trying to cover up whatever had happened and that is why they are suppressing this report.

Madam, we strongly demand that this report should be placed beore the House immediately so that we could have a discussion on the report and we could know as to, what are the issues involved. Actually we were not happy when Mr. Gyan Prakash was appointed to head the Committee. We would have liked if a Supreme Court Judge had been appointed as the Chairman of that Committee. But still we want the report of the Gyan Prakash Committee to be placed before the House. If this is not done, I am sorry to say that we cannot allow this House to function; we cannot allow the Business of the House to be transacted. Madam, I would also request you to summon the Minister concerned. Perhaps, the Prime Minister himself should come and clarify the position. Before that, the report should be tabled immediately. This is the demand I am making on behalf of my Party.

Thank you.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न हम लोगों के सामने उठ गया है और जितने भी भ्रष्टाचार के केसेज आते हैं, सरकार उनको इस तरह से कह रही है जिससे कि हम सभी अपमानित हों और इसीलिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं, इन सवालों को बार-बार उठाने के लिये। अभी हमारे मित्र विप्लव दास गुप्त जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई सरकार नहीं है। सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत भ्रष्ट सरकार है। बहुत क्लीयली लगता है कि बहुत ही भ्रष्ट सरकार है।

अभी कई बातों पर हमारे लीडर आफ अपोजिशन ने कहा कि खुदा जानता है कि क्यों ऐसा होता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर पूरा जानते हैं कि भ्रष्ट लोगों की वह रक्षा कर रहे हैं, इसमें खुदा की कोई बात नहीं है। खुदा इस बात को जानते हैं कि बहुत ही भ्रष्ट लोगों की प्रधान मंत्री रक्षा करने जा रहे हैं। बड़ा ही कलंकित हो रहे हैं। आपको एक ऐतराज है, शायद वह वैलिड हो सकता है कि अगर आप पूरी रिपोर्ट रखेंगे, तो उन अफसरों का नाम आ जायेगा, पब्लिक के सामने और उन पर बाद में कोई कार्यवाही कर सकता है। मैं यह सुझाव देता हूं कि उन अफसरों का नाम हटा दीजिये, बाकी रिपोर्ट हम लोगों को दे दीजिये, विटनेस, 1, 2, 3, 4 ऐसा कर दीजिये। हम लोग उससे काम चला लेंगे और काम जो चलेगा, वह आपको डुबो कर बैठेगा। इसीलिये हमारा कहना है कि आप अफसरों को भी बचा लीजिये और आप रिपोर्ट को भी रख लीजिये। अगर आपकी दाल में काला नहीं है, तो कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा नहीं करें।

मैं एक ही बात आपसे और कहना चाहूंगा कि आखिर सरकार किसकी बात मानती है? इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसकी बात नहीं माने। कमेटी रिपोर्ट देगी, उसकी बात नहीं मानेंगे। सी.बी. आई० ने कहा, उसकी बात

अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका कहा रिजेक्ट कर दिया तब भी मुथरा की तरह आप रखे हुए हैं कि नहीं, हम तो करते ही रहेंगे। आखिर जनता ने फैसला दिया कि आन्ध्र और कर्नाटक में अत्यन्त ही भ्रष्ट लोग हैं। फिर भी आप कहते हैं कि हमारे इकानामिक्स पॉलिसी बिलकुल दुरुस्त है?

तब तो एक ही रास्ता है कि आप बहुत भ्रष्ट हैं, इसीलिए लात मार कर आपको निकाल देते हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : (उत्तर प्रदेश) : मणिपुर में सरकार कायम करके कमी पूरी कर ली है।

श्री चतुरानन मिश्र : सरकार बनाना अलग बात है, लेकिन सरकार को कान पकड़ कर निकालना जनता के हाथ में है। यह बनाते चलें, लोग कान पकड़ कर निकालते चलेंगे। अगर आपने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार पर आप सती हीं होंगे, लार्ड बैंटिंग ने सती प्रथा खत्म कर दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सती होने पर आमादा है, यह बात समझ में नहीं आती। इसलिये हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हाऊस नहीं चलने दें, हम थोड़ा सा अमेंडमेंट इसमें चाहते हैं कि हाऊस में सिर्फ इसी सवाल को कहते रहेंगे, इसी को चलाते रहेंगे। हाऊस जरूर चलना चाहिये। आप आनन्द से यहां बैठे रहिए।

SHRI S. JAIPAL REDDY: We accept your amendment.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am thankful to you.

आप आनन्द से बैठिए, हम लोग इधर से गान करेंगे। मंत्री लोग सुनेंगे और जब तक वह थक नहीं जायेंगे, तब तक गान-बजान होता रहेगा।

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, the sugar scandal is one of the worst scandals that had taken place recently, apart from the share market scam and the fraud that had taken place in the privatisation of the public sector undertakings. (*Interruptions*) I am speaking on sugar only. I am only listing the various scandals one by one.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They were talking about a very sweet matter. What are you talking about?

SHRI MURASOLI MARAN: The sweet matter has become sour. (*Interruptions*) The sugar has become bitter. This is one of the biggest scandals which had rocked the country for a long time. We all know that the common man has been looted. It is a dacoity perpetrated on the common man. The consumer has been exploited.

Madam, recently, the former Cabinet Secretary had appeared on the T. V. and had said that the amount of fraud that had taken place was to the tune of Rs. 2,500 crores. This is not a small amount. In addition to this, more than Rs. 650 crores had been lost by way of subsidy. This is a monumental fraud which has been perpetrated on the people.

This Government wants to close its eyes. They want us also to close our eyes to this fraud. We cannot do it. We can not allow it. We want the guilty to be punished. The corrupt Ministers like Mr. Kalp Nath Rai should go and this House should have the opportunity to discuss this report.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने* कहा तो आप बिगड़ गयीं, उससे ज्यादा जोर से इन्होंने कहा। ...(व्यवधान)

उपसभापति : अल्फाज का होता है, लहजे का नहीं।

श्री शंकर दयाल सिंह : विशेष कहा था। इन्होंने संज्ञा कह दिया। ...(व्यवधान)

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Madam, I fully associate myself with what my friend, Mr. Jaipal Reddy, and others have said. This was a Committee which the Government itself had appointed against objections from the Opposition. Now, the Government is not ready to bring the report before the House. The Government is prepared to place only the findings. We do not agree. We cannot agree to this. Is this the way a Government should function? We feel that it is an insult to the House not to place the report before the House. I agree with my friends. Unless this report is placed before the House, we will not co-operate in the running of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satya Prakash Malaviya. Then, Syed Sibtey Razi.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, please permit me to say just one word.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will permit you to say two words, but at the proper time.

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): I would also like to say a word on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have your name, Mr. Mitra. Now, Shri Malaviya, please.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, जिस विषय की ओर श्री एस० जयपाल रेड्डी जी ने ध्यान दिलाना है, वह बहुत ही गंभीर है और यह सारी सरकार जनता की नजरों में दोषी हो गयी है क्योंकि चीनी घोटाले को लेकर पिछली बार भी सदन में यह मामला उठा था और जो कुछ भी खबर हम लोगों को मिली, उसके अनुसार कॉमर्स सैक्रेटरी, फूड सैक्रेटरी, तत्कालीन कैबिनेट सैक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर आफिस और वर्तमान जो खाद्य मंत्री हैं, सबको संदिग्ध दृष्टि से देखा जाने लगा । आज भी समाचार पत्र में दो खबरें प्रकाशित हुई हैं एक तो कैबिनेट सचिव श्री जफर सैफुल्ला। जी के संबंध में है जिन्होंने कोई पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा था और दूसरी खबर प्रकाशित हुई है, ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कोई पैनल बनाया गया है, वर्तमान कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है नन्दियाल, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें जो पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं वहां से हार गये हैं । यह भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है । भ्रष्टाचार की सफाई होनी चाहिए। इसके लिए जब एक कमेटी बैठाई जा रही थी उस वक्त भी आपत्ति की गई थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए लेकिन ज्ञान प्रकाश साहब की कमेटी बैठा दी गई । तब जब जांच कर ली गई तो जांच की रिपोर्ट संसद से क्यों छिपाई जा रही है, देश की जनता से क्यों छिपाई जा रही है ? गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं है वह सदन के नेता हैं । मैं चाहूंगा जब सारे सदस्य अपनी राय दे दें तो गृह मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सदन में आज ही प्रस्तुत की जायेगी और यह भी बतायें कि कब इस पर बहस होगी । क्योंकि संसद होती है बहस के लिए, सारी चीजों को उजागर करने के लिए। अगर सरकार इसको छिपाने की कोशिश करेगी तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि सारा पर्दाफाश होना चाहिए, जनता को जानकारी होनी चाहिए । अगर नहीं होगी तो हम लोग कम से कम सरकार के किसी भी काम में सदन में सहयोग नहीं देंगे । **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंह : सब लोग कह रहे हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे लेकिन हाउस चल रहा है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Self-contradiction!

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, there are two equally serious and equally shameful issues involved. The first concerns corruption and the fleecing of helpless people. The second concerns the norms of administration.

If you would kindly go through the records of this House of about a year ago, times without number we had expressed our apprehension on the floor of this House that the Public Distribution System was running dry, there was no sugar, kindly do something about it. The Government didn't bother. Madam, 25 to 30 years ago I was Marginally involved with the running of the economic policy of the Government, first, as Chairman of the Agricultural Prices Commission and then as Chief Economic Adviser to the Government. At that time the Government took particular care that 70 per cent of the sugar released to the market would is though the Public Distribution system and only 30 per cent to the trade. All that has lapsed in the course of these 25 to 30 years. Now not even 10 per cent of the distribution of sugar is through the Public Distribution System, and 90 per cent is handed over to private trade. And all that you do, whenever there is a shortage you say, we have released some extra sugar for free sale. To whom? To the traders, to the businessmen, those who cheat and fleece and exploit our people. You impose no bar on additional supplies to them. And when there is a net shortage in the country, what you do is to say that you will import. Some elements in the Government stop the import for four or five months so that prices go up a little bit more. Even when the imports come in, you have inter-departmental tussles about who will bear the cost of subsidy, and another two months go by and the prices go up further. For each kilogram of sugar that has been sold later in the last season, the extra profit the traders have made is Rs. 10 per kg., which means Rs. 10,000 per tonne. And you can make your own estimate of how much money they have made and how much money has been shared with you know whom. This is one part of the story.

The second part of the story is what is happening to the Administration, that is, the Government. The Government is a collective entity. A Minister comes to this House, makes open allegations against his own Secretary and the Cabinet Secretary, and he is not taken to task, or the Cabinet Secretary or the Secretary concerned suspended. The Prime Minister does not intervene. This is an extraordinary situation. Now, what does the poor Secretary do? Does he come to the House and defend himself? Does the Cabinet Secretary come to the House and defend himself? What did they do? They must have gone to this Commission and said what they had to say. These are not dead issues. These are the issues which are occurring around us and which cannot be made to disappear. We have to save the country. We have to save the Constitution. We have to save the administration. If this is the norm which you want to establish, then, what will happen? Not you but we will save the Constitution. We will save the country. We will throw you into the Indian Ocean. The people will through you into the Indian Ocean. Therefore, all we want is that we must know and we have the right to know what these officers have said against the Ministers and what the Ministers have said against these officers. Let the whole thing come out on the floor of this House.

Thank you, Madam.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, I want to say... (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, the ruling party benches are largely vacant. Are they deserting them? What is wrong there? Look at the benches, Madam, look at the benches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not the issue. Let him speak. He wants to say something. Sit down ...(*Interruptions*) Order, order, please. (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Pramod has gone there because the Treasury Benches are vacent... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order in the House...(*Interruptions*).

SYED SIBTEY RAZI: Mishraji, please.

और श्री चतुरानन मिश्र : वह लोग हमारे उधर आपके साथ सहमत हैं । इसीलिए (व्य की बेंचेंज खाली हैं ।..... वधान)...

श्री मोहम्मद सलीम : ...क्या बोलेंगे ?...(व्यवधान)...

شری محمد سلیم : کیا بولیں گے۔ یہ... "مداخلت"

श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ मीम अफ़जल : (उत्तर प्रदेश) : पायलट साहब आप ही बोल दीजियेग।...(व्यवधान)...

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : پائیلٹ صاحب آپ ہی بول دیجیے۔... "مداخلت"...

THE DEPUTY CHAIRMAN:

उनको बोलने दीजिए ।

Please keep quiet. Let Mr. Sibtey Razi speak.

SYED SIBTEY RAZI: Madam, I would like to submit very humbly that this is a wrong allegation that the Government wanted to cover up anything ...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. It is his right to speak in the House.

SYED SIBTEY RAZI: I would just like to remind the hon. Members, the very senior Members who just spoke about the Gian Prakash Committee Report that there is a methodology in connection with the Report submitted to the Government. You know, when a report of any commission, an inquiry commission or anything appointed by the Government is received, it is the right of the Government to look into the recommendations. For that purpose a committee has been constituted by the Government under the chairmanship of the Cabinet Secretary to look into it. Its report is time-bound. It has to be submitted by the 31st of December, 1994...(*Interruptions*)

Let him complete... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak... (*Interruptions*)

श्री सिकंदर बख्त : सरकार ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को रखना चाहती है ...(व्यवधान)...सदर साहिबा मेरा कहना है कि...

شری سکندر بخت : سرکار گیان پرکاش کمیٹی کی رپورٹ کو رکھنا چاہتی ہے۔ "مداخلت" مدر صاحبہ میرا کہنا ہے کہ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, he has a right to speak.

श्री सिकंदर बख्त : उनके बोलने से मुझे कोई एतराज नहीं है । मेरा कहना है कि जे०पी०सी० की रिपोर्ट के बाद अब तक...(व्यवधान)...हम कहते हैं... (व्यवधान)...

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

شری سکندر بخت: ان کے بولنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا کہنا ہے کہ جے۔ پی۔ سی۔ کی رپورٹ کے بعد اب تک "مداخلت" ہم کہتے ہیں ... "مداخلت"

उपसभापति : सब लोग इस पर बोले हैं... (व्यवधान)...

Everybody wants to speak.

श्री सिकंदर बख्त : बोलने का सवाल नहीं है । मेरा एतराज है कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आयी ? ...(व्यवधान)...

شری سکندر بخت: بولنے کا سوال نہیں ہے میرا اعتراض ہے کہ گیان پرکاش کمیٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی۔ ... "مداخلت"

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Never mind... (*Interruptions*) No, no. This is not correct... (*Interruptions*).

SYED SIBTEY RAZI: Nobody from us disturbed you... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, Syed Sibtey Razi has full right to speak, and I permit him.

SYED SIBTEY RAZI: Madam, my submission is that the Opposition is wrongly making very adverse inferences against the Government. The Government is examining the Report. As soon as the examination is over by the 31st of December, naturally the Government will take its own action. To say like this, that we will not permit the House to run I think, is basically against democracy. There are so many procedures. There are so many methodalogies in this House itself through which you can discuss it.

About the ATR, when we brought the ATR, they boycotted the House... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please let me speak. This is not proper. This is not the way to run the House.

You are concerned with an issue. I am quite sure that he is also concerned with the issue. He has his perception. He has a right to put it before the House... (*Interruptions*)

You cannot do like this. I won't permit this.

SYED SIBTEY RAZI: I would like to conclude only with this. It is wrong to cast aspersions on the Prime Minister and his Government. The Government is examining the Report. As soon as the report is examined totally by 31st of December, action will be taken. There is no question of not taking action. (*Interruptions*).

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): When the hon. Member says the Committee has given its report and the Government will look into it and see what action has to be taken on the report, that means the Government will take its own time till 31st of December and afterwards they will take further action. That is what the hon. Member says. Madam, we are very much concerned about it because the session of the Rajya Sabha is up to the 23rd of this month and the next session will be somewhere in February only.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him be heard, please.

SHRI G. SWAMINATHAN: So, our demand is that this report has to be placed before us early so that we will have an opportunity to discuss it. This is a matter on which we have been agitating over a period of time. The hon. Member says the last date is 31st of December. That means after the conclusion of the Rajya Sabha. Till

[Shri G. Swaminathan]

then the Committee appointed by the Government will look into it and then they will recommend action on that. You can simultaneously look into it and we can have a discussion on it. Nothing prevents the Government or the Secretaries of the Government from looking into it and making recommendations. Recommendation-making has nothing to do with the discussion at this level. The Government has also not said on what basis and under what law they will not place the Report in the House. (*Interruptions*) They should cite a precedent or say under what precedent or under what law or rule they have decided that the Report of the Committee will not be placed before this House. That is what they have not come forward with.

There was also another suggestion, which I read in the newspaper that at one stage it will be given to the leaders of the Opposition, who will see it in a particular chamber. That is only a private affair. When all the leaders can see that, Members can also see it. Leaders are elected only by the Members of the Parliament. So, everybody should have an opportunity to see it.

I have been stating during my recent speeches on this matter that an amount of Rs. 6,500 crores was involved Compared to that the Bofors issue is very small. But my friend, Mr. Murasoli Maran is saying that it is Rs. 650 crores. When you do not divulge the report of the Committee or when you do not come forward with a figure, people will go to the extent of saying that the figure is Rs. 2, 000 crores. It will become bigger and bigger scandal.

One thing about which we are very much concerned in this House is this. The performance of this Government appears to be that when a Minister is castigated for doing something, it has to go to the Cabinet and the hon. Prime Minister has to take action on that matter. When the Prime Minister does not take action on the matter, the people have to conclude that the whole Government, including the Prime Minister, is involved. That is the feeling they have developed. I do not say that the Prime Minister is involved, but if you try to protect a Minister and when all the people have been saying that there has been ample corruption in this matter and no action is taken, then the people will come to that feeling that the Government is trying to support the Minister, because the Prime Minister himself is involved. I do not want the people to have that feeling, because once they had a feeling in Andhra Pradesh, and so, even in spite of his saying that he was a Telugu *bidda* the Prime Minister has not... (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: I did not follow that point. Kindly repeat it.

SHRI G. SWAMINATHAN: I am saying if no action is taken on the Minister, the people will come to have the feeling that the Prime Minister himself is involved. Mr. Jaipal Reddy had no occasion or he did not want to say that, because he happens to be a friend of the Prime Minister. That is a different matter. I want to say that I have a great regard for the Prime Minister, And as a person who has got great regard for the Prime Minister a leading politician of the country leading the country? I should not have that kind of a feeling.

Another feeling that is also coming into the mind of the people is that this Government and this Prime Minister will not take action against anybody. That is the feeling that is being developed. Madam, supposing something wrong has been done and something has been taken, then it is the duty of the Prime Minister to take action. Otherwise, everybody will get a feeling that if one does wrong no one will take action against him. It is quite reverse to what Indira Gandhi had been doing. Those days a feeling was created that if I do something wrong I will be punished So, everybody was afraid to do anything wrong Under his Government anybody can do anything and

then he can get away because the Prime Minister takes a very long time to make up his mind or he never makes up his mind. That is the feeling that has come up. Somebody says not making up his mind is the greatest asset of the Prime Minister. I do not know why that is happening. I personally feel that this scandal is so bad that even the Bofors scandal is nothing before it.

On the Bofors scandal you have called a meeting of the party leaders to discuss this issue. Only the other day I had even asked what was the urgency in calling such a meeting when we were very much concerned with the sugar scandal. Now, they are talking about the Bofors scandal. They may be happy about it. But then they are trying to divert the attention of the people with some ulterior motive to another scandal. Madam, I personally feel that it is high time that we took up this matter immediately. The Parliament should be taken into confidence. The report should be placed on the Table of the House. It should be discussed on the floor of Parliament so that the mistrust in the minds of the people is removed. They should have confidence in the Government. It is not only that justice should be done, but justice should also appear to be done. They should see that not only justice is done but corruption is also removed as Caesar's wife was to be above suspicion. The Government should say that they are for an uncorrupt Government. If they are not able to do that, then, they will not be able to control the officers. The most important thing is that the Parliament is there to castigate not only the Ministers but the officials also. In this scandal, officials are also involved. When the Government tries to protect the Ministers, then, they would be protecting the officials also. Then, they will not be able to run the Government. In all sincerity, We want to warn the Government that they will meet their Waterloo in the coming elections. So, in their own interest they should lay a copy of the report because elections in a few more States are due and the people may defeat them again. If they want to have any credibility among the people, they should place the report on the Table of the House immediately because it is good for us, good for you and good for the country.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, रिपोर्ट दिलवाइए... (व्यवधान) गवर्नमेंट रिरपांड करे ।

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ، رپورٹ دلوایئے۔ مداخلت "گورنمنٹ رسپانڈ کرے۔

श्री शंकर दयाल सिंह : यह बड़ा गम्भीर मामला है । मैं आपसे अनरोध करता हूं कि ढाई बजे तक के लिए आप हाउस एडजर्न कर दीजिए... (व्यवधान)

उपसभापति : ईश दत्त यादव...

श्री ईश दत्त यादव : मैं तो आपका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ढाई बजे तक वे रिपोर्ट पेश करें । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाउस को एडजर्न कीजिए... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : हम लोगों को तो बोलने दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय- (उत्तर प्रदेश) : इनको भी बोलने का अधिकार है ।

श्री ईश दत्त यादव : मडम, श्री जयपाल रेड्डी जी ने और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए है, जो

[†] Transliteration in Arabic script.

श्री देश दत्त यादव
भावनाएं प्रकट की हैं, मैं उनसे अपने को संम्बद्ध करता हूं । मैं इन लोगों का समर्थन कर रहा हूं ।

मैडम, इस चीनी घोटाले को मैं इस देश का सबसे बड़ा घोटाला मानता हूं क्योंकि चीनी का संबंध इस देश के एक एक आदमी से होता है जब इस देश के अंदर चीनी घोटाला हुआ तो उस समय से लेकर आज तक देश के खाद्य मंत्री पर और देश के प्रधान मंत्री पर पूरे देश के अंदर शक की उंगली उठ रही है । पूरे देश के अंदर यह संदेश गया हुआ है कि यह सरकार घोटालों की सरकार है । यह सरकार भ्रष्ट लोगों की सरकार है । इसलिए मैडम, श्री जयपाल रेड्डी जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि ज्ञान प्रकाश समिति की जो रिपोर्ट है वह सदन में आनी चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं भी इस मांग से सहमत हूं ।

श्री सिब्ते रज़ी साहब अभी कह रहे थे कि इस रिपोर्ट को स्क्रुटिनाइज किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि सिब्ते रजी से—नेता सदन तो चले गए हैं—जो उप नेता सदन हैं, कि वह कितनी बड़ी रिपोर्ट है कि दो महीने से उस रिपोर्ट को स्क्रुटिनाइज किया जा रहा है । घंटे-दो-घंटे, एक दिन, दो दिन में उस रिपोर्ट को स्क्रुटिनाइज किया जा सकता था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है । सरकार इस घोटाले में फंसी हुई है । घोटालों पर घोटाला करने वाली सरकार के लिए यह जरुरी है—और मैं कांग्रेस सरकार के पक्ष में भी बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लोग अगर ईमानदार हैं, अगर चाहते हैं कि यह साबित करना, और सदन तथा देश के सामने यह संदेश देना चाहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ है तो उनको ज्ञान प्रकाश समिति की, ज्ञान प्रकाश आयोग की रिपोर्ट को सदन के समक्ष पेश करना चाहिए । सदन में उस पर बहस होनी चाहिए ताकि देश के सामने एक संदेश जाए वरना इस देश में ही नहीं मैडम, दुनियां में आपकी भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार की चर्चा हो रही है । इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, श्री जयपाल रेड्डी तथा दूसरे सदस्यों की बातों का समर्थन कर रहा हूं और मांग करता हूं कि इस भ्रष्ट सरकार से और देश के प्रधान मंत्री से कि . . . । अब गूंगे-बहरे मत रहिए और इस सदन के सामने उस रिपोर्ट को लेकर आइए । ताकि देश के सामने यह आ जाय क्योंकि मैडम इसमें घोटाला तो जरुर हुआ है । जब यह प्रकरण देश के सामने और जनता के सामने आया था, उस समय खाद्य सचिव, जोकि अब बदल गए हैं, उन्होंने खाद्य मंत्री के खिलाफ कुछ कहा । खाद्य मंत्री ने अपने सचिव के खिलाफ कहा और खाद्य मंत्री ने प्रधान मंत्री की ओर इशारा किया । मैडम, इसमें शक नहीं है कि चीनी के इस मामले में घोटाला है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट आज या कल इस सदन के सामने पेश की जाए ताकि उस पर चर्चा हो सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, सदन के सामने एक ही प्रश्न है . . . **(व्यवधान)** . .

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: (Tamil Nadu): Madam, what is going on? (*Interruptions*). What is the subject we are discussing? (*Interruptions*). Let them go out of the House. They are not behaving like responsible leaders. (*Interruptions*). Madam, please save the House. They are challenging the House. (*Interruptions*). They say that will not allow the House to run. (*Interruptions*).

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदया, इस समय तो आपने मुझे बोलने के लिए कहा है . . . **(व्यवधान)** . . . आप उन्हें चुप कराइए ।

उपसभापति : उनका तो माइक भी नहीं चल रहा है ।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, is this on the agenda? (*Interruptions*). I will not allow them to speak (*Interruptions*). Madam Deputy Chairman, is this on the agenda? (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Joshi Saheb, one second. He is asking a question.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, is this on the agenda? What is the subject under discussion? (*Interruptions*).

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय मैं आपके आदेश से ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदया, सदन के सामने एक ही प्रश्न है और वह प्रश्न है कि श्री ज्ञानप्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए उसके अतिरिक्त और कोई विचाराधीन नहीं है । महोदया... **(व्यवधान)** ...जितने भी घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए है... **(व्यवधान)** ... एक-एक कर के... **(व्यवधान)** ...धकेल दिया गया है । ... **(व्यवधान)** ...भ्रष्ट मंत्रियों को बचाती है, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाती है । खाद्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि... **(व्यवधान)** ...वह सिर्फ अपने पैमाने की बात जानते थे । इस सदन में वह स्वीकार कर के गए हैं कि इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए । ..... **(व्यवधान)** ..ज्ञानप्रकाश रिपोर्ट मंगाइए ।

SYED SIBTEY RAZI: Madam, there is a procedure for everything. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Go back to you seats. (*Interruptions*) This is not the way. (*Interruptions*) Just a minute. I cannot run the House like his. If you do not allow me to run the House, I will adjourn the House. (*Interruptions*) I adjourn the House till 1.30 P.M.

The House then adjourned at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

डा० मुरली मनोहर जोशी : : मैडम, मैं आपकी आज्ञा से उस समय कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ था ... **(व्यवधान)**.

उपसभापति : एक मिनट ठहरिए जरा । ... **(व्यवधान)** ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट पर कुछ **ज्ञान** होना चाहिए । ... **(व्यवधान)** ...

श्री सिकन्दर बख्त : : ज्ञानप्रकाश कमीशन की रिपोर्ट आ गई है **क्या** ? ... **(व्यवधान)** ...

شری سکندر بخت : گیان پرکاش کمیشن کی رپورٹ آگئی ہے کیا... مداخلت...

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपके आदेश से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, आपने मेरा नाम पुकारा था... **(व्यवधान)** ...

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, ज्ञानप्रकश कमीशन की रिपोर्ट आ गई है क्या ? ... **(व्यवधान)** ...

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ۔ گیان پرکاش کمیشن کی رپورٹ آگئی ہے کیا... مداخلت...

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं यह जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ ? ... **(व्यवधान)** ...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट मंगाओ । ..... **(व्यवधान)** ...

उपसभापति : मेरी बात सुनिए । ... **(व्यवधान)** ...एक मिनट । एक मिनट । ... **(व्यवधान)** ...एक मिनट मेरी बात सुनिए । ... **(व्यवधान)** ...

---

†] Transliteration in Arabic script.

श्री संघ प्रिय गौतम : ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट मंगाओ । . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभापति : एक मिनट मेरी बात तो सुनिए । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट की कापी ले कर रहे हैं क्या ?

उपसभापति : नही, नहीं, वे तो कुछ **और** ले कर रहे है । . . (**व्यवधान**) . . .

AN HON. MEMBER: No, no; nothing No, no; nothing can be laid.

श्री सिकन्दर बख्त : अगर आप ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट ले आए हैं तो बताइए ? . . . (व्यवधान) . . . ज्ञान प्रकाश कमीशन की रिपोर्ट आ गई हो तो बताइए, ? . . (**व्यवधान**) . . .

شری سکندر بخت: اگر آپ گیان پرکاش رپورٹ لے آئے ہیں تو بتایئے..."مداخلت"۔ گیان پرکاش کمیشن کی رپورٹ آگئی ہو تو بتایئے..."مداخلت"۔

उपसभापति : वह तो कुछ सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस है, उसकी बात कर रहे हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा उनसे मुलाकात कल सुबह होगी । . . . (**व्यव धान**)

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ ان سے ملاقات کل صبح ہوگی..."مداخلت"۔

श्री संघ प्रिय गौतम : घोटाले में कितना पैसा गया, वह ज्ञान कराइए। . . . (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन यादव (बिहार) : हमें ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट चाहिए । . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभापति : मेरी बात सुनेंगे । . . . (**व्यवधान**) . . . एक मिनट रुकिए । . . . (**व्यवधान**) . . . मेरी बात सुनेंगे । . . . (**व्यवधान**) . . . मुरली मनोहर जी कुछ पूछ रहे हैं मुझसे, सिकन्दर बख्त जी पूछ रहे हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, हम आपकी बात रोज सुनते हैं, आज आप हमारी सुन लें ।

उपसभापति : आप एक मिनट जरा खामोश रहिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा कुछ भी कहते रहो । . . . (**व्यवधान**) . . . सवाल यह है कि मेरे पास ज्ञान प्रकाश कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास जो लिस्टिड बिजनेस है, वही है, मैं वही चला सकती हूं । बाकी जो आपको करना है आप करिए । . . . (**व्यवधान**) . . . मैं लिस्टिड बिजनेस पर जा रही हूं । . . . (**व्यवधान**) . . .

एक माननीय सदस्य : मैडम आज वह बिजनेस नहीं चलेगा । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, बेहिसी की हद हो चुकी है, आखिर कहां जाकर रूकेगा यह मामला ?

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ بے حسی کی حد ہو چکی ہے۔ آخر کہاں جاکر رُکے گا یہ معاملہ۔

This is not the way.

इनको कहीं रोकना पड़ेगा । . . . (**व्यवधान**) . . .

सदर साहिबा, यह तो इंतहा हो चुकी है . . . (**व्यवधान**) . . .

اس کو نہیں روکنا پڑے گا..."مداخلت"۔ صدر صاحبہ یہ تو انتہا ہو چکی ہے..."مداخلت"۔

† [ ] Transliteration in Arabic script

डा० मुरली मनोहर जोशी : ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट . . . (व्यवधान) . . .

उपसभापति : उनको पेपर्स तो ले करने दीजिए । He is laying some papers.

डा० मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं, जी नहीं । . . . (व्यवधान) . . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Madam, . . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा यह कब तक चलेगा ? . . . (व्यवधान) . . .

†شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ یہ کب تک چلیگا۔ مداخلت"

This fighting needs to be broken... (*Interruptions*).

इनको रोकिए, इनको बिठाइए आप । . . . (व्यवधान) . . . आप बैठ जाइए । . . . (व्यवधान) . . .

ان کو روکیے۔ ان کو بٹھایئے۔ آپ . . . مداخلت" . . .

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, I want to make a submission. Kindly permit me... (*Interruptions*) . . . .

श्री सिकन्दर बख्त : मैडम यह क्या हो रहा है ? . . . (व्यवधान) . . .

شری سکندر بخت: میڈم یہ کیا ہو رہا ہے۔

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Madam. . (*Interruptions*) . . .

डा० मुरली मनोहर जोशी : : नहीं, उपसभापति महोदय । . . . (व्यवधान) . . .

उपसभापति: ठाकुर साहब, रुक जाइए । . . . (व्यवधान) . . .

He has sat down. ... (*Interruptions*)... He has sat down.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा यह क्या हो रहा है ? . . . (व्यवधान) . . .

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مداخلت" . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has sat down. Please keep quiet. you cannot be heard if you are making so much noise.... (*Interruptions*)...

श्री सिकन्दर बख्त : आप इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को वेल में आने के लिए । . . . (व्यवधान) . . .

شری سکندر بخت: آپ انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ویل میں آنے کیلیے۔ مداخلت"

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please .... (*Interruptions*)... Just a minute, please. You are making so much noise. If I tell him to sit down.... (*Interruptions*)...

एक मिनट चुप रहिए । . . . (व्यवधान) . . . Just a minute, please.

I want everybody to keep quiet. If you are making so much noise, — at least, you want me to be heard by the Minister — he cannot hear me. So, when I asked him — I said, "Let him lay."—, he got up to lay. I have to tell him to sit down, but he cannot hear me. ...(*Interruptions*) ... No, he cannot hear me.... (*Interruptions*)... He has sat down.

† [ ] Transliteration in Arabic script.

एक माननीय सदस्य : अगर इअरफोन लगाए होते तो सुन लेते । . . . **(व्यवधान)** . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, रिपोर्ट मंगाइए । . . . **(व्यवधान)** . . . रिपोर्ट मंगाइए रीजन दीजिए, हम ज्यादा नहीं चलने देंगे । . . . **(व्यवधान)** . . .

†شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ رپورٹ منگائیے ... "مداخلت"... رپورٹ منگائیے۔ "مداخلت" رپورٹ منگائیے۔ ریزن دیجیے۔ ہم زیادہ نہیں چلنے دیں گے... "مداخلت"...

उपसभापति : रिपोर्ट नहीं है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सिकन्दर बख्त : रिपोर्ट लाइए । दुनिया की हर चीज कारपेट के नीचे कर रहे हैं

شری سکندر بخت: رپورٹ لائیے۔ دنیا کی ہر چیز کارپیٹ کے نیچے کر رہے ہیں

There should be a limit to this. . . . *(Interruptions)* . . .

SHRI V. GOPALSAMY: It is a disrespect to the Chair.

श्री जनार्दन यादव: ज्ञान प्रकाश का रिपोर्ट चाहिए । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री संघ प्रिय गौतम : ज्ञान प्रकाश कमीशन की रिपोर्ट मंगाइए । . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI SIKANDER BAKHT: This is not the only question.

यह किस स्टेज पर तय हुआ कि उस कमेटी के ऊपर एक ओर कमेटी बैठा देंगे । . . . **(व्यवधान)** . . .

کس اسٹیج پر طے ہوا کہ اس کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بٹھا دیں گے... "مداخلت"

डा० मुरली मनोहर जोशी : सारा तरीका भ्रष्टाचार का है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सिकन्दर बख्त : एक कमेटी मुकर्रर करते हैं हाऊस की मर्जी के खिलाफ और उसके बाद एक कमेटी और बैठा देते हैं । . . . **(व्यवधान)** . . .

شری سکندر بخت: ایک کمیٹی مقرر کرتے ہیں ہاؤس کی مرضی کے خلاف اور اس کے بعد ایک کمیٹی اور بٹھا دیتے ہیں... "مداخلت"...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सारा तरीका भ्रष्टाचार को कारपेट के नीचे लाने के लिए हैं ।

एक माननीय सदस्य : उपसभापति महोदय . . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभापति : आप अपनी कुर्सी से बोलिए ना । . . . **(व्यवधान)** . . .

डा० मुरली मनोहर जोशी : जून के महीने से यह सवाल उठा हुआ है । मानसून सेशन में यह सवाल उठा था इसीलिए आपने ज्ञान प्रकाश कमेटी की बात उठाई थी । आज अब तक विंटर सेशन में उसकी रिपोर्ट नहीं आई है ।

SHRI SIKANDER BAKHT: You cannot take the whole House for granted.

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, आज इस विन्टर सेशन में उसकी रिपोर्ट देश पेश की जाए । जून से लेकर आज दिसम्बर आ गया । जून में यह सवाल उठाया गया था और इसी जून के महीने में मंत्री महोदय उठ कर बाहर चले गए थे ।

श्री सिकन्दर बख्त : इन्होंने समझ क्या रखा है कि जो जी में आए सो करें ? . . . **(व्यवधान)** . . .

†[ ] Transliteration in Arabic script.

شری سکندر بخت: انھوں نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ جو جی میں آئے کریں... "مداخلت"...

एक माननीय सदस्य : एक भी मंत्री नहीं है सदन में।

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं हो सकता है।

شری سکندر بخت: نہیں ہو سکتا ہے۔

उपसभापति : तीन-तीन मंत्री बैठे हैं ... (**व्यवधान**) ...

एक माननीय सदस्य : महोदय, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, ٹ مچ ہو گیا۔ سوری بہت ہو گیا۔

شری سکندر بخت: ... ہو گیا۔ "سوری بہت ہو گیا۔"

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I am on a point of order. (*Interruptions*)....I am on a point of order, Madam. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your point of order can be heard when there is order. (*Interruptions*) ...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Now, there is total disorder. (*Interruptions*). .

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं, नहीं, आप इनका प्वाइंट आफ ऑर्डर सुना ही दीजिए ... (**व्यवधान**)...

شری سکندر بخت: نہیں نہیں آپ ان کا پوائنٹ آف آرڈر سنا ہی دیجیے.. "مداخلت"...

डा० मुरली मनोहर जोशी : ये जे०पी० सी० की रिपोर्ट खा गये।.. (**व्यवधान**)... ये बोफोर्स स्कैंडल की रिपोर्ट खा गये, ये सी० बी० आई० की रिपोर्ट खा गए। सुखराम वाली सी०बी०आई० की रिपोर्ट खा गए। ... (**व्यवधान**))...

श्री जनार्दन यादव : मैडम हमें रिपोर्ट चाहिए। ... (**व्यवधान**)...

डा० मुरली मनोहर जोशी : ये कोई रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं। भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को बचाते हैं, भ्रष्ट मिनिस्टर्स को बचाते हैं, भ्रष्ट आफिसर्स को बचाते हैं, भ्रष्ट दलालों को बचाते हैं, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को बचाते हैं ... (**व्यवधान**)...

श्री सिकन्दर बख्त : ये कोई तरीका है कि एक कमीशन मुकर्रर करते हैं और उसके बाद दूसरा बैठा देते हैं? ... (**व्यवधान**)... इसका मतलब क्या हुआ?.. (**व्यवधान**).. हम चाहते हैं कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आए और उसको हम देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि उस को हम मान लें ... (**व्यवधान**) ...

شری سکندر بخت: یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک کمیشن مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا بٹھا دیتے ہیں... "مداخلت"... اس کا مطلب کیا ہوا... "مداخلت"... ہم چاہتے ہیں کہ گیان پرکاش کمیٹی کی رپورٹ آئے اور اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم مان لیں... "مداخلت"...

उपसभापति : आपने क्यों चिल्लाया? बंद कराओ।

श्री सिकन्दर बख्त : हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए।

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†شری سکندر بخت : ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈپٹی ... کے پاس ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैडम न लीडर आफ दि हाउस है, न कोई केबिनेट मिनिस्टर है। ... (**व्यवधान**) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, there is not a single Cabinet Minister. (*Interruptions*)... There is not a single Cabinet Minister. (*Interruptions*)

श्री सिकन्दर बख्त : इसका क्या मतलब है ? सदर साहिबा, मालूम तो होना चाहिए ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? इन्होंने समझ क्या रखा है पूरे हाउस को ? इसका मतलब क्या है ? सदर साहिब, यह बहुत अति हो चुकी है। (**व्यवधान**)) ...

†شری اسکندر بخت : اس کا کیا مطلب ہے۔ صدر صاحبہ۔ معلوم تو ہونا چاہیے "گیان پرکاش کمیٹی" کی رپورٹ کا کیا ہوا۔ انھوں نے سمجھ کیا رکھا ہے پورے ہاؤس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے۔ صدر صاحبہ۔ یہ بہت آتی ہو چکی ہے۔ "...مداخلت"...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, do we have a Government? (*Interruptions*)... Do we have a Government, Madam? (*Interruptions*)...

डा० मुरली मनोहर जोशी : सिर्फ भ्रष्ट है, सरकार नहीं है। ....(**व्यवधान**) ...

श्री सिकन्दर बख्त : भ्रष्टाचार का काम करते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे हाउस को.. ... (**व्यवधान**) ... इन्होंने समझ क्या रखा है कि जो समझ में आया सो करे ?

†شری سکندر بخت : بھرشٹاچار کا کام کرتے ہیں اس کے بعد پورے کے پورے ہاؤس کو۔ "مداخلت"... انھوں نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ جو سمجھ میں آیا سو کریں۔

डा० मुरली मनोहर जोशी : सदन का अपमान किया गया है। .. (**व्यवधान**) ..

श्री जनार्दन यादव : मैडम, जो रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट हमारे सामने भी आए। .. (**व्यवधान**) .. हमें चीनी घोटाले की ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा ये भी कोई तरीका है ? हमें रिपोर्ट चाहिए।

†شری سکندر بخت : صدر صاحبہ۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ ہمیں رپورٹ چاہیے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now what do you want me to do? (*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: You adjourn the House. (*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I want to do the business. (*Interruptions*).....

I would like you to do the other business (*Interruptions*).

SHRI ASHOK MITRA: This is the demand of the people. (*Interruptions*).

SHRI SIKANDER BAKHT: It is a very serious matter. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. (*Interruptions*). Just *a* minute. (*Interruptions*). One minute. One minute, please (*Interruptions*).

† [ ] Transliteration in Arabic script.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सरकार को कोई गरिमा है? आप सरकार की गरिमा बचाइए। ... **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप कृपया अपनी सीट पर बैठें ताकि दूसरे काम हो सकें। ... **(व्यवधान)** जरा नारेबाजी थोड़ी कम करिए। ... **(व्यवधान)** बैठिए बैठिए, खामोश रहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : (राजस्थान) : आप ऐसे लाचार हैं जैसे पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर बड़े लाचार हैं।

उपसभापति : नहीं, मैं कोई लाचार नहीं हूं।
Don't try to provoke me. I am not *lachaar* at all.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : मैडम, तभी इस हाऊस की गरिमा रहेगी। आप लाचार न बनिए।

उपसभापति : मैं बिल्कुल लाचार नहीं हूं। ... **(व्यवधान)** मेरे हाथ कमजोर नहीं हैं।
Just a minute. Please be serious. (*Interruptions*).

श्री जनार्दन यादव : गृह मंत्री जी, *के खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, आपके हाथ में है।

उपसभापति : देखिए, अगर आप ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि बाहर जाइए। जब चेयर खड़े होकर बात कर रही है तो आपको इस तरह से नारा लगाना शोभित नहीं है। ... **(व्यवधान)** सवाल यह है कि सरकार को जवाब देना है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है तो मैं क्या कर सकती हूं। लीडर आफ दि हाऊस बैठे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप डायरेक्शन दे सकती हैं। ... **(व्यवधान)**

SOME HON. MEMBERS: Madam, adjourn the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can adjourn the House. That is within my right. (*Interruptions*). I cannot reply on behalf of the Government. (*Interruptions*). What can I don? (*Interruptions*). If you don't want to do work, I will adjourn the House. (*Interruptions*). That is all. (*Interruptions*). I adjourn the House till 4 o'clock.

The House then adjourned at forty-two minutes past two of the clock.

The House re-assembled at one minute past four of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

उपसभापति : शुक्ला जी यहां बैठे हैं, कृपया उनकी बात सुनिए... **(व्यवधान)**

श्री सिकंदर बख्त : ये हाऊस का मामला है, कोई पर्सनल मामला नहीं है... **(व्यवधान)** ये हाऊस के मामले को पर्सनल मामला नहीं बना सकते **(व्यवधान)**

شری سکندر بخت: یہ ہاؤس کا معاملہ ہے۔ کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے... (مداخلت)... یہ ہاؤس کے معاملے کو پرسنل معاملہ نہیں بنا سکتے... (مداخلت)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, the whole country wants the Report to be placed on the Table of the House... (*Interruptions*).

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, इतनी देर हमने हाऊस एडजार्न किया इसलिए कि इस समस्या का समाधान हो जाए। शुक्ला जी यहां हाऊस में हैं, उनकी बात सुन लीजिए... **(व्यवधान)** मेरी बात तो सुन लीजिए। बैठ जाइए **(व्यवधान)**

*Not recorded.

देखिए आप रिपोर्ट चाहते हैं, आपको उस बारे में कुछ पूछना है। जो चीज यहां हाऊस में होनी चाहिए, जो भी हम लोगों ने ट्राई किया है चेम्बर में, शुक्ला जी को, जो कहना है वह कहेंगे, आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं। पर अगर शांति से काम हो तो अच्छा है।

श्री सिकन्दर बख्त :

एक गुजारिश करनी है बख्त कि सदर साहबा, और समाधान का जिक्र कि आपने समस्या सरकार रोजाना नयी समस्या। यह और समाधान अपोजीशन पैदा हैद करे रहे, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार करपै : है।

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ ایک گذارش کرنی ہے کہ آپ نے سمسیا اور سمادھان کا ذکر کیا ہے۔ یہ سرکار روزانہ نئی سمسیا پیدا کرے اور سمادھان اپوزیشن پیدا کرتی ہے اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔

उपसभापति : पर सुन तो लीजिए। बात तो सुननी चाहिए। देखिए पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी का क्या मतलब न एक दूसरे की बात सुनना है। मानहै नहीं मानना आपकी मरजी है। ब तो सुननी चाहिए। आपकी बात हम सुबह से सुन रहे हैं (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): But he has to answer our questions as well.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. But, let him speak....(*Interruptions*). Okay, Jaipalji, I will allow you. The thing is, since morning, I have been listening to you. It is better in a Parliamentary democracy that we listen to each other. You agree or you don't agree, that is your freedom...(*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: But he must agree to answer.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But, let him first start.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Madam, I shall be very happy to answer whatever queries the hon. Members raise. Madam, this question arose after this matter was raised in the House and the Government promised to inquire into the matter. An inquiry was ordered under an executive order. The former Comptroller and Auditor General of India, Mr. Gian Prakash, was appointed to look into this matter. All the papers were given to him. And anybody who knew anything and wanted to say anything went to him. He has prepared a Report which has been submitted to the Government. Right from the time our Constittuion came into being, no administrative reports have been laid on the Table of the House and, therefore, we have said. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow anybody who wants to raise queries.... (*Interruptions*) I will allow you.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: After I make my statement, I shall be here, as long as you want, to answer your queries. I will be at your service. Whatever you want to ask me, you may do so. Madam, this Report after having been received has been analysed by us and an unstarred question has been answered in the other House. Tomorrow is the Prime Minister's day here and it will be answered here also tomorrow. Madam, we will place a few copies of it in your Chamber and the hon. Members will have the facility of going through the Report...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: 'e will make a comprehensive state-ent before the House based on hich a discussion can follow hich will clarify any point hich is not clear to us or to them. 'e will also be very happy to answer ny query from any hon. Member of iis House. I am not taking shelter nder any technicality and I am not ying that I have the right not to y an administrative report on the able of the House. I am only say-ig that such reports are not laid on ie Table of the House and they are ot made public because it hinders endering of free and frank opinions, ee dissent in the administrative ircles. Therefore, these things are one within the administrative cir-es and within the administrative onstraints and the deductions in ur own langauge and the gist of it ill be made known. There is no itention to hide anything. I assure ou that if any Minister or any offi-ial is indicted in the report, his ame will be mentioned in the state-ient. There is no intention to hide nything. We will also make a state-ient if anybody is found guilty and ppropriate action against the guilty ill be initiated according to the aw. My request to the hon. Members s not to insist on the laying of the eport on the Table of the House ecause the quarrel on laying the re-ort on the Table of the House and eeing the report in the Chairman's hamber makes all the difference be-ause such reports on being laid on he Table of the House, become public nd, then, it becomes difficult to arry out an impartial and fearless enquiry into those matters which are of great importance. Therefore, we should give the privilege of anonymity to such people, such persons, who want to give information so that they are not harassed, they are not questioned and they are not put into trouble because they have stated all the things frankly during the enquiry. Therefore, I would again request the hon. Members to raise a discussion in the House so that all the matters are made clear and nothing remains in dark in this particular matter because we want to highlight this matter properly and there is no intention on the part of the Government to hide anything and if here is any matter involving corruption, involving misuse of public funds, we are as willing and happy to make them public as anybody else in the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have the list of names.....(*Interruptions*) ...I will call every one...(*Interruptions*)...If one person speaks at a time, I think everybody will be able to make his point. . . . .

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, एक सुझाव मेरा है। वरिष्ठ और विद्वान लोगों को सुनने से पहले हम लोगों को सुन लिया जाए। यह तो अपनी बात कहते ही रहते हैं। वरिष्ठ लोग तो कहते ही रहते हैं, हमारा नम्बर भी कभी आना चाहिए।

उपसभापति : संघ प्रिय गौतम जी, आप मेरे लिए बहुत वरिष्ठ विद्वान हैं। मैं आपको जरूर बुलाऊंगी।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Madam, please give me a minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will call you. Let there be some solution.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मैं पूरे इस सरकार के ट्रैक रिकार्ड के पसमंजर में अगर मौजूदा जो मिनिस्टर साहब ने कहा है, उसको देखूं, तो उनके ट्रैक रिकार्ड काफी है कि जो कुछ मिनिस्टर साहब ने कहा है, उसको नामंजूर कर दिया जाए। मैं इस तफसीलात में फिलहाल नहीं जाना चाहता हूं, मुख्तसर बात कहना चाह रहा हूं कि एक लफ्ज बहुत ही गलत इस्तेमाल हुआ है कि यह इन्क्वॉयरी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वॉयरी थी। हाऊस में यह किस्सा उठा है, तफसीली बातचीत हुई है, अजीबो-गरीब कनसेन्ड मिनिस्टर का बयान हुआ है, जिसका न सर था न पैर और उससे पैदा हुआ इन्क्वॉयरी का सवाल। यह कहना कि वह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वॉयरी थी, यह उस विषय से पैदा हुई इन्क्वॉयरी है, जो हाऊस में आ चुका है। इसको आप नयी डेफीनेशन देकर हाऊस में लाने से रोक नहीं सकते हैं। यह रिपोर्ट कितनी है, इस रिपोर्ट को हाऊस मंजूर करता है या नामंजूर करता है, यह रिपोर्ट भरपूर है कि नहीं, यह हाऊस तय करेगा। वहां रिपोर्ट रखने का क्या मतलब? वहां कोई फैसला होने वाला नहीं है। फैसला हाऊस को करना है कि रिपोर्ट में क्या है। एडमिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का जिक्र करना और उसको उसके साथ जोड़ने के कोई माने नहीं हैं। मैं तफसीलात में जानबूझ कर नहीं जा रहा हूं। वरना ट्रैक रिकार्ड इतना भयानक है कि हर किस्म के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश होती है और यह भी इसी तरह की कोशिश है। मैं मिनिस्टर साहब की इस तजवीज को बिल्कुल नामंजूर करता हूं।

†श्री सिकन्दर बख्त: "सदरे साहिबा"، میں پورے اس سرکار کے ٹریک ریکارڈ کے پس منظر میں اگر موجودہ منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ اس کو دیکھوں تو ان کے ٹریک ریکارڈ کافی ہے کہ جو کچھ منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ اس کو نامنظور کر دیا جائے۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ مختصر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ بہت ہی غلط استعمال ہوا ہے کہ یہ انکوائری ایڈمنسٹریٹیو انکوائری تھی۔ ہاؤس میں یہ قصہ اٹھا ہے۔ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ عجیب و غریب کنسرنڈ منسٹر کا بیان ہوا ہے۔ جس کا نہ سر تھا نہ پیر اور اس سے پیدا ہوا انکوائری کا سوال۔ یہ کہنا کہ وہ ایڈمنسٹریٹیو انکوائری تھی یہ اس وشے سے پیدا ہوئی انکوائری ہے جو ہاؤس میں آچکا ہے۔ اس کو آپ نئی ڈیفینشن دیکر ہاؤس میں لانے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ کتنی ہے۔ اس رپورٹ کو ہاؤس منظور کرتا ہے یا نامنظور کرتا ہے۔ یہ رپورٹ بھرپور ہے کہ نہیں یہ ہاؤس طے کرے گا۔ وہاں رپورٹ رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ وہاں کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے فیصلہ ہاؤس کو کرنا ہے کہ رپورٹ میں کیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹیو انکوائری کا ذکر کرنا اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کوئی معنی نہیں ہیں۔ میں تفصیلات میں جان بوجھ کر نہیں جا رہا ہوں۔ ورنہ ٹریک ریکارڈ اتنا بھیانک ہے کہ ہر قسم کے بھرشٹاچار پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور وہ بھی

† [ ] Transliteration in Arabic script.

یا مسز جانسن
کی اس تجویز کو بالکل نامنظور کرتا ہوں۔

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Deputy Chairperson, first of all, I don't agree with the Minister that this was a departmental inquiry. Mr. Gian Prakash...

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It was an administrative inquiry.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Administrative inquiry. First of all, Mr. Shukla uses these words very glibly and nobody understands all these words.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not even you!

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, I don't. The problem is I have been trained more systematically in semantics therefore, I can't follow. May I tell you, Madam, Mr. Gian Prakash did not belong to any department, did not belong to any government office. He was not competent to enquire into anything. We objected to the manner in which this non-governmental person had access to all the documents. We objected to the manner in which this non-governmental person could take evidence from people and to call it administrative inquiry is a monstrous misnomer. Today in answer to an Unstarred Question, the Government said: "The report indicates the causes for the sugar crisis as unreliable....*(Interruptions)*...

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The Lok Sabha proceedings can't be quoted in this House. ... *(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: It is a public document. .... *(Interruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: Question number 1117 has been answered in the Lok Sabha today on 14th December on behalf of the Prime Minister. It is a photocopy of the same answer. Why can't we quote from the answer given in the Lok Sabha? This is ridiculous. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: This is a public document. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: Ministers have been indicted, the Government has admitted this. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: In normal course, we don't quote from ... *(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: It is a public document. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, how can we talk about the integration of the world when these two Houses are not integrated? ... *(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Tomorrow the newspapers will publish that this is the answer given by the Government and you think we can't rely upon the statement given by the Government publicly. Do you think that we can't rely upon the version of the Government given publicly? ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole problem started when you did not allow me to complete the sentence. In the normal circumstances, we generally don't quote from the proceedings of the Lok Sabha. As the Minister has himself referred to it as an Unstarred Question, in special circumstances, I am permitting it. We should not make a precedence of having ... *(Interruptions)*... First listen to me, then your mind will be clear.

श्री सिकंदर बख्त : एक्स्ट्राआर्डिनरी हालात हैं। यह हम को सब बहानेबाजी नजर आती है। एक्स्ट्राआर्डिनरी हालात हैं। सच्चाइयां सामने आनी चाहिए चाहे किसी तरफ से आये। **(व्यवधान)**

†[شری سکندربخت : ایکسٹرا اوڈینری خالات ہوں - یہ ہم کو سب بہانے بازی نظر آتی ہے - ایکسٹرا اوڈینری حالات ہوں - سچائیاں سامنے آنی چاہئیے - چاہے کسی طرف سے آئے - مداخلت]...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, let me quote from the answer given by the Minister in full. I am not talking about the entire answer because it runs into two pages. I will quote one relevant paragraph in full for the edification of this House. The report indicates the causes for the sugar crisis as unreliable and inflated estimates of sugar production, mismanagement of available surplus stock, delay in the decision to import sugar, delay in the implementaiton of this decision and poor coordination. Certain lapses have also been identified on account of lack of clarity in the decision of the Cabinet Committee on Prices regarding imoprt of sugar, adoption of narrow departmental approach on the part of various concerned Ministries, the fact that the Cabinet Committee on Prices, the Food Minister, Civil Supplies Minister and the Cabinet Secretary did not bring the matter to the notice of the Cabinet/Prime Minister, the poor relations between the Food Minister and the Food Secretary which adversely affected the functioning of the Ministry, the absence of confidentiality regarding the decision to import sugar.

You see, I am not commenting on the report because we did not know whether this really reflects the thrust direction and content of the main report. The point I am trying to make is that it was indeed a classic example of a formless inquiry, and an anarchic inquiry. This man had no business to look into the inquiry. And, that report is being withheld from us. You allow a non-Governmental person to look into everything and you do not allow the Parliament of India to look into these.

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame.

SHRI S. JAIPAL REDDY: There would not be a more shameful thing than this. If you have given him a job to look into it, you have then perpetrated a fraud on the Constitution. Under the Constitution, he was forbidden to occupy any position. So, why should we look into the report in the Chamber of the Chairman? Now, coming to the rules...

SHRI VIDYACHARAN SHUKLA: Madam, may I make a point, if you permit?

THE DEPUTY CAHIRMAN: Yes, please.

SHRI VIDYACHARAN SHUKLA: When a retired judge of the Supreme Court or a High Court is appointed to hold an inquiry, he is also a private person. But, by an executive order whenever a private person, or anybody, is authorised to make an inquiry, he carries full authority of the Government to make such an inquiry, whether he is a retired judge or a private person, (*Interruptions*). To labour us with a point that he was a private person, since he was a retired CAG it was not up to the Government to appoint such a person is wrong. Any retired judge of the Supreme Court or a High Court or a retired high official in the Government, once appointed by an executive order for an executive or an administrative inquiry, carries full authority to conduct such inquiries and look into all the papers...

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, no. Anyway, I will never consider Mr

†[ ] Transliteration in Arabic script.

Shukla to be a legal luminary, much less an honest one at that. Whatever that be may I say that his interpretation of law is absolutely wrong and erroneous.

Under the Commissions of Inquiry Act, any one can look into the papers. There is nothing like an executive inquiry by a private person. Anyway, the point is that you have allowed him to look into all the documents. He has produced some report. Whether it is good, bad or indifferent, I do not know. I did not set any store by the report he submitted. He was chosen by the PMO to do a job. I have no confidence in his integrity and honesty at all. And you want us to look into that great report very secretly so that you can withhold it from Parliament of India. What is it that you are afraid of? And, you have referred to this report in the House last time and the impression given was that the report would be made available to the House. It is a public document. However bad the document may be, this document must be made public. The only way to make it public is to make it available to the Parliament rather than requesting us, the leaders of parties, to look at that in the Chamber of the Chairman.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Swaminathan. I think the points have been made clear and you can make a short reference.

SHRI G. SWAMINATHAN: Madam, I will make one or two points. Last year, when the discussions came up, the Minister gave an assurance. The assurance was that a Committee would be appointed and the whole thing would be gone into. So, it is an assurance by the Minister in the House. The report that has come is on the basis of that inquiry about which the assurance was given by the Minister. Any assurance made is to be an assurance to the House because the Assurances Committee is seized of your assurance. Tomorrow you cannot go back. It is a matter for the Assurances Committee to go into the question whether you have appointed the Committee and whether the report has been placed. When the report is placed, it is the property of the House. Thereafter, you have no right to say that you will give an assurance and an enquiry will be conducted and later on call it an administrative report and you will not place it on the Table of the House. Such things have never been heard. Anbody who knows the rules and procedure of the Parliament will be clear about this assurance of the Minister. I would say that you have no right to say like that. Now it is the property of the House and you have no right to say that you will not place it before the House. That is my first point.

The second point that I would like to say is that now the Minister says that the report is called the administrative report. We are not very clear about it. What do you mean by administrative report? If it is an administrative report, normally, the administrative reports are given by the officers of the Government against improprieties by other officers of the Government. Then, you may say that it is an inter-departmental enquiry on which the Government is seized of the matter and will not place it before the outsiders. Now the question raised by my hon. colleague is that the enquiry has been given to an outsider. So, it is an enquiry by the outsider, as you have rightly said either by a judge or any other officer who has retired has been asked to go into it. So, it becomes more or less a sort of judicial enquiry into the matter, as in your own words, because a retired judge or anybody who has been an officer has been given the enquiry. It is an outsider's enquiry. When it is an outsider's enquiry, it ceases to be an administrative enquiry and the Government does not have any role in the matter.

The third point that I would like to make is that whatever happens within the Committees also comes out in the newspapers, even though they are to be considered as secret. We see that anything comes up in the House and also in the Committee meetings also comes out in the Press. So, you cannot say that whatever document you place in the Chamber of the Speaker or the Chamber of the Chairman would not leak out because so many will come and see. So, naturally, the Members cannot be prevented from talking about it outside and it has to go in the newspapers also. You want to protect somebody who has been a witness to that. Now-a-days, Madam, people want transparency in every record and every transaction of the Government. The word 'Government' is becoming transparent. Now, you want to cover up the matter. You do not want to become transparent, I do not understand your logic. Yesterday it appeared that the Government was of the view that only the leaders could see it and now you say that Members can see it only in the Chamber of the Chairman. I do not know why you are saying this. Once a Member sees it in the Chamber of the Chairman, can he take notes on that? You have to clarify that. When I want to speak, I may like to have a note on this in the Chamber of the Chairman, without which I will not be able to speak. I cannot keep everything in my memory. If we really want to speak on that report, then we should be aware of what is contained in that report. I do not know how many pages it contains, 200, 300 or more. How do I carry the whole gamut? So, I may have to sit there for some time and take notes and then I have refer to the notes and bring them outside. How can you deny me that right as a Member of Parliament not to take notes, because I should grasp it and then come back? These are the questions that you have to answer. I feel that by your argument that you will place it only in the Chamber of the Chairman and Members can see it as 'secret' and nothing will be talked about it outside and the Government will not be transparent, the Government is trying to cover up something. People would be very unhappy about the attitude that you are taking. The Members of the Opposition are so unhappy that you are not taking the Members of Parliament into confidence. I am sorry to say this on behalf of my party.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the Government has exhausted... *(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam,.... *(Interruptions)*.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, allow us to speak. *(Interruptions)*

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): They cannot shut us out like that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I seek your protection to speak. *(Interruptions)*

श्री सिकन्दर बख्त : रिपोर्ट लाइए हाउस में.. (व्यवधान) कोई बहस वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप। अगर वे बैठ जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे ... (व्यवधान) हेन दे आर नाट सिटिंग... (व्यवधान)

†شری سکندر بخت: رپورٹ لائیے ہاؤس میں... "مداخلت"... کوئی بحث وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کیا کر رہے ہیں آپ۔ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے... "مداخلت"... "وہیں دے آر ناٹ سیٹنگ"... "مداخلت"...

†[ ] Transliteration in Arabic script.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हम किसी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले हैं..(**व्यवधान**) आप रिपोर्ट रखिए ...(**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): They cannot shut us out We have also our views on this· (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mathur Saheb, please. (*Interruptions*) You have a right to say your viewpoint· Nobody is shutting you out· I think, people from the back benches also want to speak· There are some other people who want to speak. Congress members are very much Members of this House.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, you have called him· You have allowed him. Let him speak. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a second, please. They are very much Members of this House. They have as much right as you have to speak. How can you say they cannot speak?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Nobody says that· (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr· Ashok Mitra, there is no need to get agitated because I am not agitated. You are not understanding the whole situation. I am sorry, I cannot explain·

SHRI ASHOK MITRA: The names are given...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. What I said is that after Mr. Gurudas Das Gupta, he will speak· (*Interruptions*)

DR· BIPLAB DASGUPTA: Why can't you allow him?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): This is not a discussion.... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue with me on this issue that you should speak first because that will be impossible. (*Interruptions*) They have a right· You cannot stop that. (*Interruptions*)

श्री संघ प्रिय गौतम : हमें आपका भी भाषण नहीं चाहिए...(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह कोई तरीका नहीं है...(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : यह तो कल तक चलता रहेगा। यह डिबेट कल तक चलती रहेगी (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not the way· Just because you want the report others have no right to speak? Mr· Satya Prakash Malaviya wants to speak· I should permit him also. Mr. Hanumanthappa wanted to speak· This is not proper· It is not dignified· There are other lady Members who want to speak· She raised her hand. How can you say that you only should speak and everybody should keep quiet? No, no. This is not the way·

श्री संघ प्रिय गौतम : आप हमको भी समय दीजिए और सीनियर लीडर्स को भी...(**व्यवधान**) आप हर वक्त बोलते रहते हैं। हमको ही समय नहीं मिलता है। आप सब लोग बोलते हैं, हर विषय पर आप ही लोग बोलते हैं...(**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is this? He goes on speaking. Madam, Deputy Chairperson, frankly speaking, we have exhausted out Parliamentary patience because ...

SHRI JAGESH DESAI: You have patience?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The reason for it, Madam, is this. The Government got itself involved in a number of scandals, As a result, there is a cloud of suspicion now hanging over those who are there in the citadel of power. Therefore, the present situation cannot be compared with any of the previous conventions that you have. Convention is built. Convention is broken. (*Interruptions*) Even if I concede that there is a convention, let there be a new convention. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Do you concede? (*Interruptions*) Let him say that. Let him say whether he concedes. There is a convention in the House that a report that has been submitted to the Prime Minister....(*Interruptions*) Madam, he admits that there is a convention. Let him say that. Let it be on record.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Even if I concede that there is a convention, there is a need for setting up a new convention because the situation is unprecedented. The corruption is unprecedented. The charges of involvement of Ministers are unprecedented, one after another. Therefore, the Government's position is extremely vulnerable. When you are speaking of conventions, please also consider the vulnerable position which the Government is in today.

Please look at the writing on the wall in Andhra Pradesh and Karnataka. It is a writing on the wall for you and it is in your own interest that this could of suspicion is removed. In order to remove this cloud of suspicion, it is appropriate that the Members of Parliament are given the complete information about the enquiry. It does not matter whether it was an executive enquiry or an administrative enquiry. It is a ridiculous argument on formality because the entire nation is seized with one after another scam. Therefore, we must know the facts because the people must be punished. We want the report. Why? Because the people involved in corruption must be punished and the Government must exonerate itself of the charge of getting involved in corruption. For this, we want the report to be tabled.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vayalar Ravi.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. I have called Shri Ravi.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Just one minute, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I had allowed you. (*Interruptions*). I had allowed you in the morning. Now, let Shri Vayalar Ravi speak. Let him also have his say. Maybe, you can react on his observations.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam Deputy Chairperson,.... (*Interruptions*).

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, बहस की कोई बात नहीं है।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, बहस काहे के लिए? यहां मिनिस्टर साहब ने अपनी बात कह दी और हमारा कहना यह है कि हमें वह मंजूर नहीं है। हमारी मांग है कि आप रिपोर्ट लाइए। हाउस में रिपोर्ट लाइए। तो अब बहस काहे पर हो रही है? काहे की बहस हो रही है? रिपोर्ट लाइए मेहरबानी कर के।

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ بحث کا ہیں کیلئے۔ یہاں منسٹر صاحب نے اپنی بات کہہ دی اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں وہ منظور نہیں ہے۔ ہماری مانگ ہے کہ آپ رپورٹ لایئے۔ ہاؤس میں رپورٹ لایئے۔ تو اب بحث کا ہیں پر ہوگی۔ رپورٹ لایئے مہربانی کرکے۔

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not a monopoly of the Opposition alone. The ruling party Members have also a right to speak in this House. (*Interruptions*).

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: As a Member, he has got the right. He has got equal right. (*Interruptions*).

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, यहां मंत्री जी ने सरकार की तरफ से कुछ बात रखी और उन्होंने कहा कि वह तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो अब क्या जवाब देंगे। ... **(व्यवधान)** ...

شری محمد سلیم: میڈم۔ یہ منتری جی نے سرکار کی طرف سے کچھ بات رکھی اور انھوں نے کہا کہ وہ تمام پرشنوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وپکش انکی بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو یہ کیا جواب دینگے ... "مداخلت" ...

श्री सिकंदर बख्त : रिपोर्ट लाइए। रिपोर्ट लाइए।

شری سکندر بخت: رپورٹ لایئے۔ رپورٹ لایئے۔

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: As a Member of the Party, as a Member of the House, he has got full right. (*Interruptions*).

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, I am exercising my right as a Member of this House. (*Interruptions*).

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Whatever Mr. Ravi wants to say, he should be allowed to say. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: We have got every right to speak in this House. (*Interruptions*). Madam, I am on a point of order... (*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will adjourn the House ... (*Interruptions*)... The House is adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-seven minutes past four of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 15th December, 1994.

† [ ] Transliteration in Arabic script.